राजधानी जागरण

भवनहीन निकायों को मिलेगा 'घर'

जागरण ब्यूरो, पटना : शहरी इलाकों में साफ-सफाई, नागरिक सुविधाओं से लेकर लोगों को घर मुहैया कराने वाले अनेक नगर निकाय खुद बिना 'घर' के हैं। ऐसे भवनहीन निकायों का अब अपना 'घर' होगा।

ऐसे 19 नगर परिषदों एवं 21 नगर पंचायतों के प्रशासनिक भवन के लिए पुनरीक्षित योजना को मंजूरी दी गई है। नगर पंचायतों के भवन निर्माण पर प्रति भवन 60 लाख 9 हजार रुपये का खर्च आएगा, जबकि नगर परिषदों के प्रशासनिक भवन को पूरा करने के लिए 72.35 लाख की दर से योजना को मंजूरी देने की कार्रवाई चल रही है। नगर परिषदों में तीन पूर्णिया, कटिहार और मुंगेर तो अब नगर निगम में परिवर्तित हो चुके हैं। नगर विकास मंत्री के अनुसार 42 नगर परिषदों में से 37 नगर परिषदों एवं 86 नगर पंचायतों में से 63 नगर पंचायतों में प्रशासनिक भवन निर्माण कराया जा रहा है। प्रथम चरण में 21 नगर पंचायतों एवं 19 नगर परिषदों की योजनाओं को पुनरीक्षित करते हुए इसी वित्तीय वर्ष में समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। शेष निकायों के लिए अगले वित्तीय वर्ष में राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

जिन निकायों के बन रहे भवन

- **नगर पंचायत** : मुरलीगंज, बनमनखी, नवगछिया, बरबीघा, चकिया, बहादुरगंज, दाउदनगर, वीरपुर, मनेर, झंझारपुर, कहलगांव, कांटी, बरौली, कसबा, झाझा, बेलसंड, विक्रमगंज, मैरवा, रफीगंज एवं डुमरा।
- **नगर परिषद** : किशनगंज, अररिया, बेतिया, मधुबनी, पूर्णिया (अब नगर निगम), कटिहार, (अब नगर निगम), सुपौल, हाजीपुर, सासाराम, बक्सर, डिहरी , डालमियानगर, नरकटियागंज, फारबिसगंज, मसौढ़ी, खगड़िया, भभुआ, समस्तीपुर, औरंगाबाद एवं मुंगेर (अब नगर निगम)।

ऐसी रहेगी व्यवस्था

विभाग के निर्देश के अनुसार भवन जी प्लस टू होंगे। ग्राउंड फ्लोर पर दुकान नहीं होंगे। बल्कि सेवा प्रदायी कंप्यूटर सेंटर, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र देने वाले केंद्र, जन शिकायत निष्पादन केंद्र व बहुद्देशीय हाल होगा। प्रथम तल पर जन प्रतिनिधियों, कार्यालय आदि के लिए कक्ष होंगे तो दूसरे तल पर कार्यालय।

> "नगर निकायों को सुदृढ़ करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से सभी भवनहीन निकायों को अपना प्रशासनिक भवन की योजना स्वीकृत की जा रही है। इसी साल 19 नगर परिषदों एवं 21 नगर पंचायतों में प्रशासनिक भवन निर्माण का काम पूरा करने का लक्ष्य है।
>
> **डा. प्रेम कुमार, मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग**